# REET 2025 LEVEL-1

# वंदन बैच

# EVS

Demo 02

# सामाजिक बुराइयां

LIVE 27-12-2024 04:00 PM

# TIME TABLE

# REET 2025 LEVEL-1 & 2

# वंदन बैच

MATHS
L-1 07AM

GEOGRAPHY
L-2 10 AM

हिंदी
L-1&2 11 AM

CDP
L-1&2 02 PM

ENGLISH
L-1&2 03 PM

संस्कृत
L-1&2 03 PM

EVS
L-1 04 PM

PHYSICS
L-2 04 PM

MATHS
L-2 05 PM

POLITY
L-2 07 PM

CHEM+ BIO
L-2 07 PM

HISTORY
L-2 08 PM

Registration Starts from
**23rd DEC**

Classes Start from
**26th DEC**

JOIN US ON

DOWNLOAD THE
RWA APP NOW

Google Play

REET 2025
LEVEL-1 & 2
ROJGAR
With
ANKIT
वंदन बैच
Features
Live Classes
Doubt Group
Class Notes PDF
Mock Test
Experienced Teachers
₹999/-
30% off
Coupon Code: REET30
₹699/-
Registration Starts from
23rd DEC
Classes Start from
26th DEC
JOIN US ON
DOWNLOAD THE
Google Play

# कोर्स कैसे PURCHASE करें ?

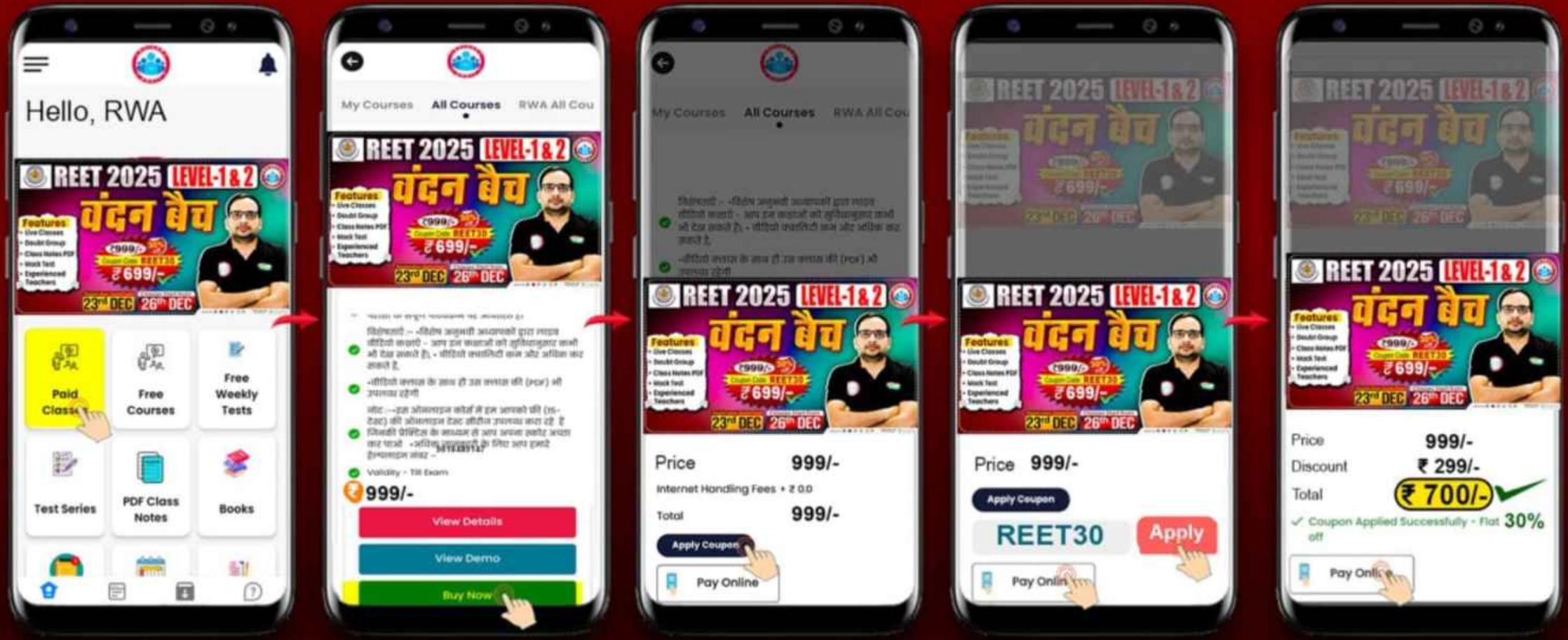

# सामाजिक बुराइयां

# बाल विवाह
# (Child Marriage)

भारतीय कानून के मुताबिक, जब किसी लड़की की उम्र 18 साल से कम या किसी लड़के की उम्र 21 साल से कम होती है, तो उस विवाह को बाल विवाह माना जाता है |

**According to Indian law, when a girl is less than 18 years of age or a boy is less than 21 years of age, then that marriage is considered child marriage.**

# कारण (Reasons)

## बाल विवाह के कारण/Reasons for child marriage

- शिक्षा की कमी
- Lack of education
- गरीबी
- Poverty
- दहेज प्रथा
- Dowry system

- लड़की की शादी को माता पिता द्वारा बोझ समझना |
- Parents considering girl's marriage as a burden.
- रूढ़िवादी परम्पराओं का होना |
- Presence of conservative traditions.

# परिणाम (Result)

## दुष्परिणाम/Adverse effects

- जनसंख्या वृद्धि |
- Population growth
- शिशु व मातृ मृत्यु दर में वृद्धि |
- Increase in infant and maternal mortality rate.
- लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव |
- Adverse effect on girls' education.
- बच्चों का शारीरिक वं मानसिक विकास अवरुद्ध |
- Physical and mental development of children is obstructed.

# रोकथाम का प्रयास

## बाल विवाह रोकथाम के प्रयास:/Efforts to prevent child marriage:

- राज. में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत जोधपुर थी ।
- Jodhpur was the first state to ban child marriage in Rajasthan.
- बाल विवाह रोकथाम हेतु सर्वप्रथम 1929 में हरविलास शारदा ने बाल विवाह निरोधक अधि. प्रस्तावित किया, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह अधि. 1 अप्रैल, 1930 को लागू हुआ, जिसके तहत लड़कियों की आयु 14 वर्ष व लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई (विवाह के लिये)
- For the prevention of child marriage, Harvilas Sharda first proposed the Child Marriage Prevention Act in 1929, which is known as Sharda Act. This Act. It came into force on 1 April 1930, under which the age of girls was fixed at 14 years and that of boys at 18 years.

❖ 1978 में शारदा एक्ट में संशोधन कर विवाह योग्य आयु को बढ़ाकर लड़कियों व लड़कों के लिए क्रमश: 18 व 21 वर्ष कर दी गयी।

❖ In 1978, the Sharda Act was amended and the marriageable age was raised to 18 and 21 years for girls and boys respectively.

❖ 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया तथा नया अधि. बाल विवाह निषेध अधि. पारित किया जिसे 1 नव. 2007 को लागू किया गया था।

❖ In 2006, the Sharda Act was repealed and a new Act was enacted. Prohibition of Child Marriage Act" was passed which came into force on 1st November 2007.

- सजा का प्रावधान - 2 वर्ष की सजा अथवा 1 लाख रु का जुर्माना अथवा दोनों।
- Punishment provision ÷ Imprisonment of 2 years or fine of Rs 1 lakh or both.

## बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021/Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021

महिलाओं की विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए लोकसभा में संशोधन पेश किया गया था। दिसंबर 2021 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रस्तावित विधेयक को विस्तृत जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया था ।

An amendment was introduced in the Lok Sabha to increase the marriageable age of women from 18 to 21 years. In December 2021, Union Minister for Women and Child Development Smriti Irani referred the proposed bill to the Parliamentary Standing Committee for detailed scrutiny.

# दहेज प्रथा
# (dowry System)

## भारत में दहेज प्रथा / DOWRY SYSTEM

भारत में दहेज प्रथा टिकाऊ सामान, नकदी या चल संपत्ति को संदर्भित करता है जो दुल्हन का परिवार दूल्हे, उसके माता-पिता और उसके रिश्तेदारों को शादी की शर्त के रूप में देता है। Dowry दहेज को हिंदी में दहेज़ और उर्दू में जहेज़ कहा जाता है। दहेज प्रथा दुल्हन के परिवार पर भारी वित्तीय बोझ डाल सकती है। कुछ मामलों में, दहेज प्रथा महिलाओं के खिलाफ अपराध की ओर ले जाती है, जिसमें भावनात्मक दुर्व्यवहार और चोट से लेकर मृत्यु भी शामिल है।

Dowry system in India refers to durable goods, cash or movable property that the bride's family gives to the groom, his parents and his relatives as a condition of marriage. Dowry is called Dahej in Hindi and Jahez in Urdu. The dowry system can place a heavy financial burden on the bride's family. In some cases, the dowry system can lead to the marriage of women. It leads to crime against the mother and father, which includes emotional abuse and injury to death.

# दुष्परिणाम (Bad effects)

**दहेज प्रथा के दुष्परिणाम-** ऋणग्रस्तता, महिलाओं पर अत्याचार, समाज में भ्रूण हत्या व कन्यावध को प्रोत्साहन तथा बेमेल विवाह ।

**Evil effects of dowry system -** indebtedness, atrocities on women, encouragement of female foeticide and infanticide in the society and mismatched marriages

**कारण Reasons**

- आर्थिक लालच **Economic greed**
- लड़की को बोझ समझना **Considering girl as a burden**
- स्त्रियों की निम्न दशा **Low status of women**
- समाज की पितृसत्तात्मक संरचना **Patriarchal structure of society**

## रोकने के उपाय Measures to stop it

- 20 मई 1961 को "दहेज निषेध अधि." पारित किया। इसके तहत दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध घोषित किये गये।
- On 20 May 1961, the "Dowry Prohibition Act" was passed. Under this, both giving and taking dowry were declared crimes.

- यह अधि. 1 जुलाई 1961 को जम्मू-कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू हुआ।
- This Act came into force in the rest of India except Jammu and Kashmir on 1 July 1961.

- 1986 में इस अधि. में संशोधन करते हुए दहेज को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया।
- In 1986, this Act was amended and dowry was declared a non-bailable offence
- सजा का प्रावधान : 5 वर्ष की सजा अथवा 15000 जुर्माना अथवा दोनों |
- Punishment provision: 5 years imprisonment or 15000 rupees fine or both.
- धारा 498 (A) :- दहेज प्रताड़ना के दोषियों को 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है |
- Section 498 (A):- There is a provision of 3 years imprisonment for those guilty of dowry harassment.

- धारा 406 :- तलाक के बाद महिला को स्त्रीधन न लौटाये जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है ।
- Section 406:- There is a provision of 3 years imprisonment for not returning the stridhan to the woman after divorce
- धारा 304 (B) :- यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर विवाहिता की मृत्यु हो जाए और जाँच में ये दहेज हत्या साबित हो जाती है। तो अपराधियों को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है ।
- Section 304 (B):- If the married woman dies within 7 years of marriage and it is proved to be dowry murder in the investigation. Then there is a provision of punishment ranging from 7 years to life imprisonment for the culprits.